शब्दबाणों का प्रहार

सिवनी

राष्ट्रबाण

संपादकः संजय बघेल

मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय अखबार

बुधवार 11 जून 2025 • वर्ष : 10 • अंक : 74 • पृष्ठ : 08 • मूल्य : 5.00 रुपए

www.facebook.com/rashtrabaan www.twitter.com/rashtrabaan

न्यूज ब्रीफ

चुनाव आयोग ने कमल हासन का नामांकन स्वीकार किया

नईदिल्ली। चुनाव आयोग ने एक्टर-पॉलिटिशियन कमल हासन का नोमिनेशन स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मक्कल नीधि मय्यम पार्टी के चीफ कमल हासन के अलावा 5 नेताओं का राज्यसभा सांसद बनना लगभग तय है। तमिलनाडु की 6 राज्यसभा सीटों के सांसद 24 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने वाले सांसदों में एमडीएमके के वाइको और पीएमके के अंबुमणि रामदास शामिल हैं। 6 सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होगी। हालांकि, सभी 6 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाना तय है।

गाजियाबाद में सूटकेस में महिला की लाश

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 28 साल की महिला की लाश सूटकेस में मिली है। सूटकेस चादर में लपेटकर फेंका गया था। मंगलवार सुबह 8 बजे इसे कुत्ते खींच रहे थे। आसपास के लोगों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस, महिला पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंची है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। गले पर भी निशान है। नाक से खून बहा है। पुलिस मान रही कि गला दबाकर हत्या की गई।

लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें: खड़गे

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने ने लिखा- डिप्टी स्पीकर का पद दो लोकसभा टर्म (17वीं और अब 18वीं) से खाली है। यह पद खाली रहना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है और लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं।

आग लगी, बालकनी से छलांग लगाने से पिता, दो बच्चों की मौत

नईदिल्ली। दिल्ली के द्वारका सेक्टर-13 स्थित शबद अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल के एक फ्लैट में मंगलवार सुबह आग लग गई। फ्लैट के अंदर एक पिता अपने दो बच्चों (एक लड़का-एक लड़की) के साथ फंस गए थे। बचने के लिए 10 साल के दोनों बच्चों ने बालकनी से छलांग लगाई। उनके साथ उनके पिता यश यादव (35) ने भी छलांग लगा दी। तीनों को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि उन्हें सुबह 10:01 बजे इस घटना की सूचना मिली।

राजा रघुवंशी मर्डर केस: सोनम ने 4 लाख का दिया था ऑफर, फिर राजा के मर्डर वाली जगह पर बढ़ा कर किया 20 लाख

इंदौर। राष्ट्रबाण

राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी, और दोनों अपने हनीमून पर मेघालय आए थे। वे 23 मई को नोंग्रियाट गांव में एक होमस्टे से चेक आउट करने के कुछ घंटों बाद ही गायब हो गए। इस गांव से 20 किमी दूर ही राजा का शव मिला था।

इंदौर के राजा रघुवंशी के मर्डर मिस्ट्री में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस सूत्रों ने नया खुलासा किया है कि सोनम रघुवंशी ने सात दिन पहले बने पति यानी राजा रघुवंशी की हत्या के लिए शुरू में चार लाख रुपये की सुपारी दी थी ताकि भाड़े पर हत्यारे खोजे जा सकें और रास्ते से राजा का सफाया किया जा सके लेकिन चंद दिनों बाद ही उस रकम को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था। शीर्ष पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोनम ने ही रघुवंशी के शव को मेघालय में एक खाई में फेंकने में अन्य आरोपियों की मदद की थी।

राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके (जिसे चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है) में एक झरने के पास एक खाई में मिली थी, जब वह अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय पहुंचा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोनम द्वारा किराए पर लिए गए हत्यारों ने सबसे पहले नवविवाहित जोड़े से बेंगलुरु में मुलाकात की थी, जहां से उन्होंने पूर्वोत्तर के लिए अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी। चूंकि पीड़ित और आरोपी एक ही शहर से थे, इसलिए इस दौरान उनकी बातचीत भी होती रही।

4 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया किलिंग अमाउंट

सूत्रों ने बताया कि उसी समय सोनम ने थके होने का नाटक किया और अपने पति और हत्यारों से काफी पीछे चली गई। जब वे एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, तो सोनम ने कथित तौर पर उन लोगों से अपने पति को मारने के लिए कहा। हालांकि, सूत्रों के अनुसार हत्यारों ने उसे मारने से इनकार कर दिया और कहा कि वे भी थके हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद सोनम रघुवंशी ने कथित तौर पर अपनी पेशकश को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने राजा पर हमला बोल दिया और और उसकी हत्या कर दी। कथित तौर पर इसके बाद सोनम ने ही राजा की लाश नीचे खाई में फेंकने में मदद की। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, उसके सिर पर दो गहरे घाव थे।

राजा की हत्या के बाद सोनम ट्रेन से इंदौर आई, किराए के कमरे में रुकी थी; मेघालय पुलिस सोनम को लेकर रवाना

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी (29) हत्याकांड में मंगलवार को नया खुलासा हुआ। पति राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को शिलॉन्ग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। शिलॉन्ग एसपी विवेक स्येम ने बताया कि सोनम इंदौर आने के बाद किराए के कमरे में रुकी थी। सोनम को एक ड्राइवर ने

वाराणसी में ड्रॉप किया था, जहां से वह गाजीपुर पहुंची थी। इस बीच, इंदौर में क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस की टीम आज आरोपी विशाल को लेकर उसके घर पहुंची। वारदात के समय पहने गए कपड़े जब्त किए। क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद्र यादव ने बताया कि राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल ने ही किया था। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर पटना एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है। टीम पहले कोलकाता पहुंचेगी फिर गुवाहाटी होते हुए शिलॉन्ग पहुंचेगी। सोनम करीब 6 घंटे तक पटना के थाने में रही, वह टेबल पर सिर रखकर रोती रही। चाय तक नहीं पी।

गाइड ने राजा-सोनम के साथ आए एक संदिग्ध को पहचाना

मेघालय के मावलखियात में स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीडी ने इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के साथ आए संदिग्धों में से एक की पहचान कर ली है। मंगलवार को पुलिस ने उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई थी। बता दें कि अल्बर्ट ने ही राजा-सोनम के लापता होने के दिन तीन और लोगों की मौजूदगी का दावा किया था। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अपराधी आखिरकार सलाखों के पीछे हैं। हम निर्दोष साबित हुए हैं। जिन लोगों ने सोहरा और उसके लोगों की हिंसक छवि को खराब करने की कोशिश की थी, वे अब बेनकाब हो गए हैं।

गाइड ने कहा था- चार पुरुष आगे चल रहे थे

- अल्बर्ट ने बताया था कि उन्होंने 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास दंपती को तीन पुरुषों के साथ नोंग्रियाट से मावलखियाट तक 3,000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा था।
- राजा सहित चार पुरुष आगे चल रहे थे, जबकि महिला पीछे थी। चारों पुरुष हिंदी में बातचीत कर रहे थे।
- अल्बर्ट ने 22 मई को उन्हें नोंग्रियाट तक चलने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया।
- दंपती ने भा वानसाई नामक एक अन्य गाइड को काम पर रखा, जिसने उन्हें शिपारा होमस्टे पर छोड़ दिया था।

हथियार ऑनलाइन मंगवाया, आरोपियों से सोनम ने कहा था- मार दो, 3 अहम पॉइंट्स

1. पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने जिस हथियार 'डाव' (छोटी कुल्हाड़ी) से राजा को मारा, वो गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगाया था। आरोपी शिलॉन्ग में सोनम-राजा के होम स्टे से एक किमी दूर होटल में ठहरे थे। इनके नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती, लोकेशन भेज देती।
2. 23 मई को सोनम फोटो शूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में ही तीनों आरोपी राजा से मिले। हिंदी में बात की और साथ चल दिए। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम ने चिल्लाकर कहा- मार दो इसे।
3. हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़े। आरोपी भी अपने-अपने घर ट्रेन से रवाना हुए। सोनम अकेली वाराणसी गई। यहां बस स्टैंड पर दो लोग उसे छोड़ने गए।

मेघालय के मंत्री बोले- सोनम और राजा का परिवार माफी मांगे

मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने कहा, हम राजा और सोनम रघुवंशी के परिवारों से माफी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेघालय और इसके लोगों की छवि को धूमिल किया है। अन्यथा हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। कपल के गायब होने के बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने उनके अपहरण और हत्या की आशंका जताई थी। कहा था कि स्थानीय लोगों का हाथ हो सकता है। मेघालय सरकार तथ्यों को दबाना चाहती है।

मेघालय के लोग आज शाम को निकालेंगे कैंडल मार्च

मेघालय में सोहरा क्षेत्र के लोग इंदौर के राजा रघुवंशी की याद में मंगलवार शाम 6.30 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे। यहां के लोगों ने बैनर-पोस्टर के जरिए अपील की है कि मीडिया बिना वेरीफाई किए कोई रिपोर्ट पब्लिश न करें। सोहरा के लोग पर्यटकों के साथ है, क्रिमिनल नहीं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि सोहरा आकर यहां की खूबसूरती को एन्जॉय करें।

पति की हत्या के बाद ट्रेन से इंदौर आई थी सोनम

राजा रघुवंशी हत्याकांड में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम रघुवंशी पति की हत्या के बाद 25 मई को शिलॉन्ग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। इंदौर में वह किराए के कमरे में रुकी थी। उसे एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया था, जहां से वह गाजीपुर पहुंची थी। शिलॉन्ग एसपी विवेक स्येम ने भास्कर रिपोर्टर योगेश पाण्डे से बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि की।

वन-वे टिकट की योजना सोनम रघुवंशी की ही थी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हनीमून के लिए मेघालय की वन-वे टिकट की योजना सोनम रघुवंशी की ही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि हनीमून के दौरान कुशवाहा मेघालय नहीं गया था, लेकिन उसने पर्दे के पीछे रहकर सारी योजना बनाई थी और वह लगातार सोनम रघुवंशी के संपर्क में था। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि सभी आरोपी नवविवाहित जोड़े का पीछा करते हुए पहले 21 मई को गुवाहाटी पहुंचे, जहां वे होटल के पास रुके और फिर 22 मई को शिलांग पहुंचे। इसके अगले ही दिन यानी 23 मई को उनलोगों ने राजा की हत्या कर दी। 23 मई को सोनम और राजा रघुवंशी झरने को देखने के लिए एक खड़ी चोटी पर गए थे, जहां हत्यारे उनका पीछा कर रहे थे।

बनास-नदी में डूबने से जयपुर के 8 युवकों की मौत

पिकनिक मनाने गए थे, एक-दूसरे को बचाने में डूब गए, मरने वालों में जीजा-साले भी

टोंक। एजेंसी

टोंक की बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। तीन युवकों को बचा लिया गया। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा था। मरने वाले सभी लोग जयपुर के रहने वाले थे। ये पिकनिक मनाने गए थे। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि हादसा आज (मंगलवार) दोपहर सदर थाना क्षेत्र के कच्चा बांध, पुराना बनास पुलिया पर हुआ। 11 युवक नदी में डूबे थे, 8 की मौत हो गई और तीन को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। जयपुर पुलिस से कॉन्टैक्ट किया गया है।

एसपी ने बताया कि ये सभी दोस्त थे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि इनमें से कुछ युवक नहाने के लिए नदी में उतरे थे और डूबने लगे। इन्हें बचाने के लिए बाकी दोस्त भी नदी में उतर गए और वे हादसे का शिकार हो गए। सभी की उम्र 25 से 30 साल है। शवों को सआदत हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया है।

भारतीय से बदसलूकी पर अमेरिका बोला- अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं, वैध तरीके से आएं तो स्वागत

एयरपोर्ट पर छात्र को पटका फिर इंडिया भेजा था

वॉशिंगटन डीसी। एजेंसी

अमेरिका के न्यूजर्सी में भारतीय छात्र को जमीन पर पटकने, हथकड़ी लगाने और डिपोर्ट करने के मुद्दे पर भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को बयान दिया। दूतावास ने कहा कि अमेरिका में अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिकी दूतावास ने X पर लिखा- अमेरिका अपने देश में वैध यात्रियों का स्वागत करता है। हम अवैध एंट्री, वीजा का

दुरूपयोग या अमेरिकी कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कुणाल जैन ने रविवार को इस घटना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जैन ने एक्स पर लिखा- मैंने न्यूअर्क एयरपोर्ट पर एक युवा भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर, रोते हुए, अपराधी की तरह ट्रीट होते देखा। जैन ने बताया कि छात्र हरियाणवी में कह रहा था, मैं पागल नहीं हूं, ये लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।

ऑस्ट्रिया के स्कूल में गोलीबारी, अब तक 11 छात्रों की मौत

28 घायल; संदिग्ध हमलावर स्कूल का छात्र, बॉडी मिली

वियना। एजेंसी

ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में मंगलवार सुबह एक हाई स्कूल में फायरिंग की घटना हुई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए। उनमें से चार की हालत बेहद गंभीर है। कुछ लोगों के सिर में भी गोली लगी है।

पुलिस ने इलाके में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वे वहां से

दूर रहें। ऑस्ट्रियाई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे बोर्ग ड्रेयर्सचुटजेनगैस हाई स्कूल के अंदर गोलियों की आवाजें सुनी गईं। इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध हमलावर शायद उसी स्कूल का छात्र था और उसने खुद को गोली मारकर जान ले ली।

पहलगाम आतंकी हमला लापरवाही का नतीजा

ममता ने विधानसभा में पूछा- हमले वाली जगह पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी; कहा- मोदी सरकार इस्तीफा दे

कोलकाता। एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को सशस्त्र बलों की प्रशंसा करने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान सीएम ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा- पहलगाम आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा था। ममता ने पूछा- आतंकी हमले वाली जगह पर सुरक्षाकर्मी क्यों नदारद थे।

ममता ने कहा कि भाजपा सशस्त्र बलों की वीरता का

राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, भाजपा सरकार को चले जाना चाहिए क्योंकि वह देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी केवल अपने बारे में विज्ञापन देने में बिजी हैं।

ममता ने कहा- आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या पंथ नहीं होता; हम इसका समर्थन नहीं करते। आतंकवादियों को सबक सिखाने की जरूरत थी, हम सशस्त्र बलों की बहादुरी को सलाम करते हैं।

ममता ने विधानसभा में यह भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर किया की गई एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) को वापस लेने का एक अच्छा मौका था।

केंद्र सरकार ने क्यों लगाई पाबंदी? ग्रामीण रोजगार पर क्या असर

पहली बार मनरेगा योजना में खर्च की सीमा तय

नईदिल्ली। एजेंसी

देशभर के ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने वाली महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) पर पहली बार केंद्र सरकार ने खर्च सीमा की पाबंदी लगाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मनरेगा के तहत होने वाले खर्च को कुल वार्षिक आवंटन का 60 फीसदी तक सीमित कर दिया है। अब तक इस योजना में खर्च की कोई सीमा तय नहीं थी और यह

मांग के आधार पर संचालित योजना रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को सूचित किया है कि अब इस योजना के तहत होने वाले खर्च को मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना के तहत लाया जाएगा, जो एक खर्च पर नियंत्रण का एक तरीका है। हालांकि, इस योजना को अब तक इस तरह के नियंत्रण उपायों से छूट मिली हुई थी।

पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने भेजी चिट्ठी: बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों के तहत कैश फ्लो और गैर जरूरी उधारी को कम करने और उसे नियंत्रित करने के लिए 2017 में मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना की शुरुआत की थी लेकिन मनरेगा स्कीम को इससे बाहर रखा था। ऐसा कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को निर्देश दे दिए थे कि वह मनरेगा को भी मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना ढांचे में शामिल करे। पिछले महीने 29 मई को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बावत ग्रामीण विकास मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर 60 फीसदी खर्च की सीमा तय करने के फैसले से अवगत करा दिया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना नामंजूर

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के बजट विभाग को मनरेगा के लिए एक मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना पेश की थी, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 की पहली दो तिमाही में अधिक खर्च सीमा का प्रस्ताव दिया था लेकिन वित्त मंत्रालय ने उसे खारिज कर दिया है और उसे 60 फीसदी तक तय कर दिया है। यानी छह महीने के अंदर सितंबर तक कुल बजटीय आवंटन का 60 फीसदी ही खर्च किया जा सकता है।

संपादकीय

कुशलता बढ़ाइए

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में जन्मदर बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने फाइनैंशल इन्सेंटिव्स देने की योजना बनाई है। चंद्रबाबू के इस फैसले के पीछे सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक कारण हैं।

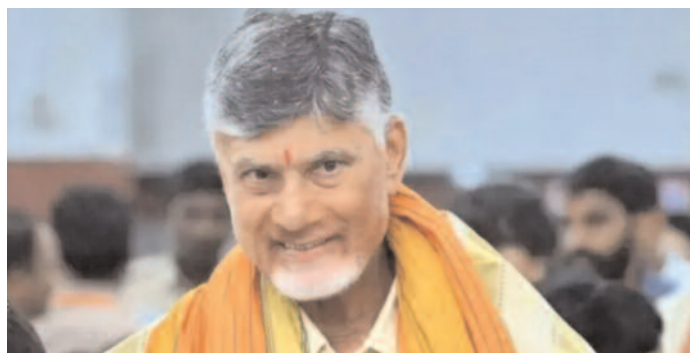

कनाडा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में जन्मदर बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने फाइनैंशल इन्सेंटिव्स देने की योजना बनाई है। चंद्रबाबू के इस फैसले के पीछे सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक कारण हैं। हालांकि आबादी के मामले में चीजें इस तरह से काम नहीं करती हैं।

विरोधी विचार: नायडू का कहना है कि परिवार जितना बड़ा होगा, उसे उतना ही ज्यादा आर्थिक अनुदान मिलेगा। इससे पहले वह महिलाओं के लिए कितनी भी बार मैटर्निटी लीव और वर्कप्लेस पर बच्चों के लिए सेंटर जैसे नियम बना चुके हैं। विडंबना है कि इसी आंध्र प्रदेश में ऐसे लोगों को निकाय चुनावों में खड़े होने से रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया था, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं।

सीटों की चिंता: आंध्र की पॉलिसी में यह बदलाव आया कैसे? इसका जवाब बहुत कुछ संख्या बल की राजनीति में है। आंध्र समेत दक्षिण के सभी राज्यों में यह चिंता है कि कम आबादी की वजह से उनकी राजनीतिक हैसियत में कमी आई है। परिसीमन पर दक्षिण का विरोध इसी वजह से है कि उत्तर के राज्यों की तुलना में उनके यहां लोकसभा की सीटें कम बढ़ सकती हैं और इससे देश की सियासत में वह कमजोर पड़ जाएगा। चंद्रबाबू इसी के चलते दक्षिणी राज्यों से अपनी जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं।

चीन का उदाहरण: हालांकि जनसंख्या इस तरह स्टॉप-स्टार्ट मोड में काम नहीं करती और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। पेइचिंग ने करीब चार दशकों तक वन चाइल्ड पॉलिसी का सख्ती से पालन किया। जब इसका असर उसकी वर्कफोर्स पर पड़ा, तो 2015 में उसने दो बच्चों और फिर तीन बच्चों तक की छूट दे दी, लेकिन इससे उसकी जन्मदर पर खास फर्क नहीं पड़ा।

जन्म दर में गिरावट: दक्षिण का डर कि उसकी आबादी गिर रही है, तस्वीर को अधूरा देखना है। असल में पूरे देश में जन्म दर में गिरावट आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि देश में फर्टिलिटी रेट 2.0 है यानी हर कपल औसतन दो बच्चे पैदा कर रहा है। सबसे कम, 1.4 टीएफआर दिल्ली और पश्चिम बंगाल का था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में फर्टिलिटी रेट 1.5, जबकि तेलंगाना और कर्नाटक में 1.6 दर्ज की गई थी।

असल लक्ष्य: शिक्षा के साथ आई जागरूकता के कारण पिछले दशक से आबादी में बढ़ोत्तरी नियंत्रण में आई है। भारत के सामने समस्या जनसंख्या घटने की नहीं, बल्कि यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह स्किल्ड बनाया जाए ताकि वे भी विकास में साझीदार हों और उनके जीवन स्तर में सुधार आए।

मणिपुर में वर्ष 2023 से जातीय संघर्ष चल रहा है। तब से हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है और मैतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के हजारों लोगों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा है।

मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा की आग, साल 2023 के जातीय संघर्ष से जुड़े हुए हैं तार

मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से हिंसा भड़क उठी है। जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इससे पहले भी राज्य को कई मर्तबा हिंसा की त्रासदी झेलनी पड़ी है। इस बार हिंसा का प्रत्यक्ष कारण भले ही मैतेई समुदाय के एक नेता समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी है, लेकिन इसके तार वर्ष 2023 में हुई जातीय हिंसा से ही जुड़े हुए हैं।

सवाल है कि जातीय आधार पर लोगों के गुस्से का ज्वार आखिर शांत क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को भावनात्मक रूप से भड़काने के पीछे कौन है? ऐसी क्या वजह है कि लोग किसी सामान्य घटना को भी समुदाय से जोड़ लेते हैं और सड़कों पर उतर कर उग्र व्यवहार करने लगते हैं?

हिंसा की वजह से ही एन बीरेन सिंह को गंवानी पड़ी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी

मणिपुर में वर्ष 2023 से जातीय संघर्ष चल रहा है। तब से हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है और मैतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के हजारों लोगों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा है। हिंसा का सिलसिला जारी रहने की वजह से एन बीरेन सिंह को इस साल

फरवरी में मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था। उसके बाद से यहां राष्ट्रपति शासन लागू है। तब से राज्य में हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। माना जा रहा था कि अब हालत सामान्य हो रहे हैं। मगर राज्य के सिर पर शांति का यह सेहरा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया।

दरअसल, सीबीआइ ने गत रविवार को मैतेई संगठन अरंमबाई तेंगोल (एटी) के सदस्य कानन सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा चार अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। इन सब पर वर्ष 2023 में हुई हिंसा से संबंधित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। जांच एजंसी का कहना है कि आरोपी कानन सिंह मणिपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल था, लेकिन उसे मार्च 2025 को हथियारों की तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था।

किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती हिंसा

सीबीआइ की इस कार्रवाई के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने के आरोप में कार्रवाई होती है, तो इसे समुदाय विशेष से जोड़ कर क्यों देखा जा रहा है। जांच के जरिए इस बात का पता लगाने की जरूरत है कि कहीं कोई लोगों की भावनाओं को भड़का कर अपने निजी स्वार्थ हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? साथ ही प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे जन आक्रोश को शांत करने के लिए संबंधित लोगों के साथ तत्काल संवाद कायम करें।

प्रदर्शनकारियों को भी यह बात समझनी होगी कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। अगर उनके नेता पर लगे आरोपों को लेकर किसी तरह का संदेह है, तो न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। सड़कों पर उत्पात मचाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कुछ हासिल नहीं होगा।

पति-पत्नी दोनों को एक दूसरे पर होना चाहिए भरोसा

भारत में विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसमें जीवन भर के रिश्ते की बुनियाद पड़ती है। एक विश्वास के साथ युगल अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करता है। पति और पत्नी दोनों को भरोसा होता है कि जब भी वे मुश्किल डगर पर होंगे, तो एक-दूसरे को संभाल लेंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी शादी के एक हफ्ते बाद अपनी मधुर स्मृतियों को सहेजने के लिए पत्नी के साथ जब मेघालय गए होंगे, तब उन्हें पता नहीं होगा कि वे कभी लौट कर घर नहीं आएंगे और उनका हनीमून एक भयावह घटना में बदल जाएगा।

शिलांग में पर्यटन के दौरान यह नवयुगल लापता हो गया था। इसके बाद एक खाई में राजा का शव मिला। तब से उनकी पत्नी सोनम गायब थी। पुलिस उसे ढूंढ़ती रही। सात दिन बाद पता चला कि वह गाजीपुर में है। इसके बाद देश को झकझोर देने वाली इस घटना से पर्दा उठ गया। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही पति की हत्या भाड़े के हत्यारों से कराई है। उसने आत्मसमर्पण जरूर कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर उसे आपत्ति थी, तो उसने यह शादी ही क्यों की?

मारपीट और हत्या के मामले बढ़े

पिछले एक अरसे में नवदंपतियों के बीच बढ़ते अविश्वास और मतभेद के कारण कलह, मारपीट और तलाक के मामले बढ़े हैं। जीवन भर एक-दूसरे का साथ निभाने का जो वचन दिया जाता है, वह कुछ दिनों या महीनों में टूटने लगता है। दोनों पक्ष के परिवारों के समझाने-बुझाने पर भी कई बार पति-पत्नी साथ नहीं रहते और नवयुगल का घरौंदा बसने से पहले ही उजड़ जाता है।

मगर सवाल है कि वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से नवदंपतियों में टकराव की नौबत पैदा होती है। इसे समझना होगा। दरअसल, इसके पीछे अति महत्त्वाकांक्षा, सुख-सुविधाएं और अवैध संबंध तो हैं ही, वहीं परिवार के दबाव में अनिच्छा से की गई शादी भी बड़ी वजह है।

व्यापार

कंपनी को 3 गुना हुआ मुनाफा, 6 महीने से बंद पड़ा है शेयर, अब दी गई एक नई जानकारी

कंपनी के शेयरों में 30 दिसंबर 2024 के बाद से कारोबार नहीं हुआ है। इसका अंतिम ट्रेडिंग प्राइस 10.28 रुपये है। यानी पिछले 6 महीने से इस शेयर में कोई कारोबार नहीं हुआ है।

ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों की लगातार ट्रेडिंग बंद है। कंपनी के शेयरों में 30 दिसंबर 2024 के बाद से कारोबार नहीं हुआ है। इसका अंतिम ट्रेडिंग प्राइस 10.28 रुपये है। यानी पिछले 6 महीने से इस शेयर में कोई कारोबार नहीं हुआ है। सेबी ने इसके कारोबार पर रोक लगाई थी। अब कंपनी ने बाजार को नई जानकारी दी है। कंपनी ने शेयर बाजार से अपने कार्यालय का पता बदलने की जानकारी शेयर की है।

कंपनी ने क्या कहा?

सेबी विनियम, 2015 के विनियमन 30 के अनुसार, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का रजिस्टर्ड पता 9 जून, 2025 से बदल जाएगा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया हैः पुराना पंजीकृत पता - फ्लोरः 5, फेयरील्ड बाय मैरियट, रोड नंबर 2, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद - 500032, तेलंगाना। नया पंजीकृत पता (9 जून, 2025 से प्रभावी)- 6-3-1086/वीजीटी/101/बी, विस्टा ग्रैंड टावर्स, पहली मंजिल, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद - 500082, तेलंगाना।

कंपनी ने दी यह जानकारी

कंपनी ने आगे कहा था कि उसे तेलंगाना उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिली है, जिसने प्रथम दृष्टया साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए सेबी द्वारा लगाए गए कुछ दंडों को निलंबित कर दिया है। आगे की ओर देखते हुए, ब्राइटकॉम समूह डिजिटल विज्ञापन और एआई में अभिनव समाधान लॉन्च करने,एनपीएसी, ईयू और उत्तरी अमेरिका जैसे प्रमुख वैश्विक बाजारों में विस्तार करने और कॉर्पोरेट प्रशासन और निवेशक संचार को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है।

मार्च तिमाही के नतीजे

डिजिटल मार्केटिंग और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता ब्राइटकॉम ग्रुप ने 31 मई को कहा कि मार्च तिमाही में उसका समेकित कर पश्चात लाभ (पीएटी) एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में तीन गुना बढ़कर 120.68 करोड़ रुपये हो गया, जो मुख्य रूप से उच्च राजस्व के कारण हुआ। कंपनी के बयान के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही में कंपनी ने 37.46 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। ब्राइटकॉम ग्रुप की परिचालन आय क्यू4एफवाय25 में 987.48 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 704.60 करोड़ रुपये थी। बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, वित्त वर्ष 25 के लिए समेकित पीएटी 710.03 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 687.52 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। ब्राइटकॉम ने वित्त वर्ष 2024 में 4,662.25 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,146.66 करोड़ रुपये की समेकित परिचालन आय हासिल की।

आईपीओ के लिए 26 साल पुरानी कंपनी की बड़ी तैयारी, 17 निवेश बैंकों से हो रही बात

हाल ही में इस कंपनी ने अपने मेगा आईपीओ के लिए 17 निवेश बैंकों से बातचीत की है। बता दें कि यह एक ज्वाइंट वेंचर है जो 26 वर्षों से अस्तित्व में है।

दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी-आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में इस कंपनी ने अपने मेगा आईपीओ के लिए 17 निवेश बैंकों से बातचीत की है। बता दें कि यह एक ज्वाइंट वेंचर है जो 26 वर्षों से अस्तित्व में है। ज्वाइंट वेंचर में आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रिटेन की प्रूडेंशियल पीएलसी के साथ गठजोड़ किया था।

क्या है डिटेल

मनीकंट्रोल के सूत्र ने बताया कि निवेश बैंकों और वकीलों सहित सभी सलाहकारों के साथ पिछले सप्ताह इस डील की शुरुआत की गई। यह आईपीओ पूरी तरह से प्रूडेंशियल द्वारा ओएफएस या बिक्री के लिए प्रस्ताव होगा, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की कोई भागीदारी नहीं होगी। जून के अंत या जुलाई की शुरुआत तक ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने की योजना है।

एक अन्य सूत्र ने कहा कि इस बड़े इश्यू के प्रस्तावित साइज पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन लगभग 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। इस सूत्र ने कहा कि बाद में आईपीओ साइज बदल सकता है। सूत्र के मुताबिक आईपीओ के लॉन्च के करीब आने पर अधिक स्पष्टता सामने आएगी। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही तक आईपीओ के आने की उम्मीद है।

17 निवेश बैंकों में कौन-कौन शामिल

निवेश बैंकों के बड़े सिंडिकेट में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और सिटी शामिल हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, आईआईएफएल कैपिटल, नोमुरा सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, एवेंडस कैपिटल, नुवामा, बीएनपी पारिबा, सीएलएसए सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल भी हैं। यह दूसरा ऐसा आईपीओ होगा जिसमें इतने निवेश बैंक शामिल होंगे। इससे पहले भारती इंफ्राटेल ने अपने आईपीओ के लिए 13 निवेश बैंकों को नियुक्त किया था। इसके अलावा कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास और सिडली को प्रस्तावित आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

आईसीआईसीआई की ये कंपनियां हैं लिस्ट

आईसीआईसीआई बैंक के अलावा, आईसीआईसीआई समूह की कई अन्य कंपनियां भी सूचीबद्ध हैं। इनमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज शामिल हैं।

1 पर 7 शेयर फ्री दे रही है यह कंपनी, साथ ही डिविडेंड भी

इंटरलाइनिंग टेक्सटाइल के आयात, डिस्ट्रिब्यूटर और कारोबार में शामिल कंपनी शाइन फैशन (इंडिया) लिमिटेड के शेयर इन दिनों लगातार फोकस में हैं।इंटरलाइनिंग टेक्सटाइल के आयात, डिस्ट्रिब्यूटर और कारोबार में शामिल कंपनी शाइन फैशन (इंडिया) लिमिटेड के शेयर इन दिनों लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में आज मंगलवार को 5त्न से अधिक चढ़ गए और 422 रुपये पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान है। दरअसल, कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को 7:1 के रेशियो में बोनस शेयर दे रही है। साथ ही कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। अब कंपनी ने इसके रिकॉर्ड डेट पर एक ऐलान किया है।

क्या है डिटेल

शेयर बाजार को जानकारी देते हुए कंपनी ने कहा है कि 06 जून 2025 को आयोजित कंपनी की पिछली बोर्ड मीटिंग में तय की गई 4 जुलाई, 2025 की रिकॉर्ड तिथि केवल डिविडेंड की घोषणा के लिए तय की गई है, न कि बोनस शेयर जारी करने के लिए। इसलिए, हम बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड तिथि वापस लेते हैं और उचित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर इसकी घोषणा अलग से की जाएगी।

डिविडेंड दे रही है कंपनी

बता दें कि शाइन फैशन ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है, ÷बोर्ड मेंबर ने 06.05.2025 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूरी तरह से भुगतान किए गए 5 रुपये (2.5त्न) के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 12.50 पैसे का डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जो आगामी 6वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

एफडी से सेविंग अकाउंट तक, एचडीएफसी बैंक ने जमा पैसे पर दिया बड़ा झटका

एचडीएफसी बैंक ने अपनी सावधि जमा (एफडी) और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक अब विभिन्न एफडी अवधियों पर कम ब्याज दर प्रदान करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो दर में कटौती के बाद सेविंग करने वाले निवेशकों को कई बड़े बैंकों ने झटका दिया है। इनमें से एक प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक है। बैंक ने अपनी सावधि जमा (एफडी) और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक अब विभिन्न एफडी अवधियों पर कम ब्याज दर प्रदान करता है। एफडी पर ब्याज दर 3प्रतिशत से 7.20प्रतिशत के बीच है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को सभी अवधियों में 0.50प्रतिशत अधिक ब्याज मिलना जारी है।

किस अवधि के एफडी की कितनी ब्याज दर

7-14 दिन की अवधि के लिए सामान्य नागरिकों को एफडी पर 2.75प्रतिशत ब्याज और सीनियर सिटीजंस को 3.25प्रतिशत ब्याज

मिलता है। वहीं, 30-45 दिन की अवधि के लिए क्रमशः 3.25 प्रतिशत और 3.75प्रतिशत ब्याज मिलता है। 90 दिन से 6 महीने तक की अवधि के लिए 4.25प्रतिशत और 4.75प्रतिशत ब्याज दर मिलता है। 18 महीने से 21 महीने की अवधि के लिए बैंक सामान्य नागरिकों को 6.60प्रतिशत ब्याज और सीनियर सिटीजन को 7.10प्रतिशत ब्याज देता है।

बैंक ने सेविंग अकाउंट वाले निवेशकों को भी झटका दिया है। बैंक ने 50 लाख रुपये से अधिक के खाते के बैलेंस के लिए ब्याज दर को 3.50प्रतिशत से घटाकर 3.00प्रतिशत कर दिया है। 50 लाख रुपये से कम के बैलेंस पर 3.00प्रतिशत ब्याज मिलना जारी रहेगा।

लोन लेने वाले ग्राहकों को राहतः हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में विभिन्न अवधियों में 0.10 प्रतिशत की कटौती की थी। कटौती के साथ, एक दिन की और एक महीने की दरें 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.90 प्रतिशत रह गई हैं। तीन महीने की दर 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.95 प्रतिशत हो गई है, जबकि छह महीने और एक साल की दर 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9.05 प्रतिशत रह गई है। बता दें कि आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में अपेक्षा से अधिक 0.50 प्रतिशत की कटौती की और बैंकों को उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने हेतु अप्रत्याशित रूप से नकद आरक्षित अनुपात में कटौती की।

युवाओं में रोष, मुँह ताकते रहें कुछ बड़बोले नेता

लालबर्रा। राष्ट्रबाण

प्रदेश सरकार के द्वारा विगत माह विभिन्न विकासखण्डों में नवीन शासकीय आईटीआई की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें लालबर्रा विकासखंड में भी शासकीय आईटीआई स्वीकृत किया गया है। जिसके लिए शासन के निर्देशानुसार तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा नवीन शासकीय आईटीआई खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। जिसके लिए बालाघाट स्थित शासकीय आईटीआई के अधिकारी एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन एवं वैकल्पिक रूप से कक्षाएं संचालित करने के लिए शासकीय भवनों का निरीक्षण कर नवीन सत्र 2025-26 में कक्षाएं संचालित करने के लिए भवन चिन्हांकित भी किया था और अस्थाई रूप से शासकीय उत्कृष्ट स्कूल लालबर्रा के सामने स्थित सामुदायिक भवन में संचालित किया जाना था। किन्तु यह पूरी प्रक्रिया स्पष्ट तौर से हवा हवाई ही नजर आ रही है क्योंकि वर्तमान में तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा आईटीआई में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और यह पूरी प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विभाग की साइट (पोर्टल) पर ऑनलाइन की जा रही है। जिसमें विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आईटीआई चयनित करने के विकल्प रहे हैं। जिसमें लालबर्रा के युवाओं के द्वारा नवीन आईटीआई स्वीकृत होने की बात सुनने पर जब प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सेंटर में पहुंच रहे हैं तो इस प्रवेश प्रक्रिया के दौरान संस्थान चयन सूची में उन्हें लालबर्रा शासकीय आईटीआई का किसी तरह का कोई भी नाम दिखाई नहीं दे रहा। जिससे वह निराश नजर आ रहे है और मजबूरन जिले की अन्य आईटीआई को चयनित कर इस प्रवेश प्रक्रिया का फॉर्म पूर्ण कर रहे हैं।

निरिक्षण पर निरीक्षण नतीजा सिफ़र

आपको बता दे कि म.प्र. शासन के द्वारा लालबर्रा विकासखंड में नवीन आईटीआई स्वीकृति का पत्र जारी होते ही क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे एवं संबंधित विभाग के आला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा लालबर्रा मुख्यालय पहुंचकर शासकीय भूमियों का निरीक्षण किया गया था एवं नवीन आईटीआई भवन, छात्रावास निर्माण सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया और जब तक भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत नहीं हो जाती। तब तक वैकल्पिक रूप से आईटीआई किसी शासकीय भवन में संचालित करने के लिए मुख्यालय के विभिन्न सामुदायिक भवनों का निरीक्षण भी किया गया था। जिसके पश्चात शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के सामने स्थित सामुदायिक भवन में अस्थाई रूप से वर्ष 2025-26 में आईटीआई का संचालित करने के लिए सहमति बनी थी।

परंतु जैसे ही शासन की ओर से आईटीआई में प्रवेश के लिए नवीन सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई तो उसमें संस्थान चयन के दौरान लालबर्रा आईटीआई का नाम दिखाई नहीं दे रहा हैं। जिससे युवाओं में शासन प्रशासन की प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। जबकि शासन के द्वारा नवीन आईटीआई स्वीकृत होने से लालबर्रा के युवाओं में उत्साह व एक नई उमंग थी कि वे अब हमारे लालबर्रा नगर मुख्यालय में आईटीआई खुलने से हम अपने ही क्षेत्र में तकनीकी पढ़ाई कर डिग्री लेंगे और अपना स्वयं का रोजगार या व्यापार, उद्योग जगत में नौकरी करेगें परंतु इन युवाओं की उम्मीद पर अब स्पष्ट रूप से पानी फिरता दिखाई दे रहा है क्योंकि शासन के द्वारा लालबर्रा में आईटीआई की स्वीकृति कागजों में ही की गई है। जमीनी स्तर पर किसी तरह की कोई भी प्रक्रिया अब तक प्रारंभ नहीं हो पाई है जिससे शासन की या नवीन आईटीआई स्वीकृत 2025-26 में शुरू होने की घोषणाएं झूठी प्रतीत हो रही है।

नवीन सत्र में प्रवेश के लिए पोर्टल से गायब लालबर्रा शासकीय आईटीआई का नाम

लालबर्रा आईटीआई मामले में भाजपा व कांग्रेस दोनों फेल

आईटीआई के लिए जमीन का निरिक्षण करते जनप्रतिनिधि।

आईटीआई प्रारम्भ करने नहीं मिली प्रशासकीय स्वीकृति

वहीं शासकीय आईटीआई बालाघाट के जिम्मेदारों का कहना है कि शासन स्तर से लालबर्रा में शासकीय आईटीआई वर्ष 2025-26 से शुरू करने की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई है जिसके कारण पोर्टल में लालबर्रा शासकीय आईटीआई नहीं दिखा रहा है, प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद ही लालबर्रा में आईटीआई खुलेगी। जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि लालबर्रा में वर्ष 2025-26 में आईटीआई नहीं खुलेगा और पूर्व में भाजपा एवं विपक्ष के द्वारा जिस तरह से लालबर्रा में शासन से आईटीआई की स्वीकृति दिलाने एवं इसी सत्र से प्रारंभ करने की जो बात कही जा रही थी वे बड़बोले नेता मुँह ताकते ही रह गये और लालबर्रा में आईटीआई खुलने की बात हवा-हवाई नजर आ रही है और लालबर्रा आईटीआई मामले में भाजपा व कांग्रेस दोनों फेल दिखाई दे रही है।

खाली पड़ी बिल्डिंग में आईटीआई लगाने वैकल्पिक भवन।

आईटीआई नहीं खुलने से युवा वर्ग में रोष

वहीं आईटीआई में पंजीयन करवाने की अंतिम तिथि 16 जून है। जबकि नवीन आईटीआई स्वीकृत होने के संबंध में जब शासन से पत्र जारी किये गये थे। तब पक्ष-विपक्ष के द्वारा लालबर्रा में शासकीय आईटीआई की स्वीकृति दिलवाने का श्रेय लेने की होड़ मची हुई थी और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे थे। किन्तु वास्तविक स्थिति में लालबर्रा में शासकीय आईटीआई की स्वीकृति कागजों में ही सिमट कर रह गई है। ऐसी स्थिति में वे युवा जिन्होंने वर्तमान में कक्षा 10 वीं और 12 वीं उत्तीर्ण की है और लालबर्रा में ही शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेकर व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे। उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने पर आईटीआई चयन के लिए जब उनके द्वारा विकल्प देखे गये तो उसमें लालबर्रा आईटीआई का कहीं से कहीं तक कोई भी नाम दिखाई नहीं दिया। जिससे वह मायूस होकर जिले के अन्य शासकीय आईटीआई संस्थान में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा पूर्ण करनी पड़ेगी जिससे उन्हे आर्थिक परेशानियों से जुझना पड़ेगा। साथ ही लालबर्रा में आईटीआई वर्ष 2025-26 से नहीं खुलने से रोष व्याप्त है।

राष्ट्रबाण इम्पेक्ट

एमएसपी से कम और एमआरपी से अधिक पर नहीं किया जाएगा मदिरा का विक्रय

8 मदिरा दुकानों पर हुई टेस्ट पर्चेस की कार्यवाही

राष्ट्रबाण
एमआरपी रेट से अधिक दामों में शराब बिकवा रहे ठेकेदार
शराब दुकानों के पास में ही अवैध अहातों का संचालन, सरकार की पाबंदी के बाद भी जिम्मेदार विभाग है बेसुध

राष्ट्रबाण में प्रकाशित खबर।

निर्धारित दर पर शराब विक्रय नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

बालाघाट। राष्ट्रबाण

कलेक्टर मृणाल मीना ने जिले में एमएसपी से कम एवं एमआरपी से अधिक पर मदिरा विक्रय करने वाले वृत्त प्रभारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। शुक्रवार को आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये निर्देशित किये गए है कि जिले में स्थित मदिरा दुकानों द्वारा न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) से कम एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने वालो के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सहायक आबकारी आयुक्त सुरेंद्र कुमार उरांव ने बताया कि शनिवार को जिले में संचालित 8 मदिरा दुकानों पर टेस्ट पर्चेस की कार्यवाही की गई। जिनमें एक मदिरा दुकानों पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय होना पाया गया। जिसमें विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही सभी मदिरा दुकानों पर एमएसपी एवं एमआरपी की जानकारी देने वाला क्यूआर कोड भी चस्पा किया जा रहा है।

बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू की वार्षिक परीक्षाएं प्रारम्भ

बालाघाट। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू छात्रों कि वार्षिक परीक्षाएं प्रारम्भ हो गई है। जिससे महिला छात्रों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार शासकीय पीजी कालेज लांजी में सिंगोला कि रहने वाली श्रीमति लक्ष्वंती ढेकवारे अंतिम वर्ष की बीएसडब्ल्यू की छात्रा अपने 10 दिवस के नवजात शिशु को लेकर परीक्षा में शामिल हुई।जिससे कि वह अन्य महाविद्यालयीन छात्राओ के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनी। विवाह एवं संतान के बाद भी यदि महिला चाहे तो अपने तमाम तरक्की के रास्ते स्वयं बना सकती है। उन्होंने विवाह होने के बाद परिवार कि देखभाल घरेलू कामकाज इत्यादि के साथ बीएसडब्ल्यू कोर्स में नियमित रही। उनके शिक्षा के प्रति रूचि देख उनके पति एवं सासु मां भी पूरा सहयोग कर रही है।

भटेरा पंचायत में विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

लैंगिक एवं सायबर अपराधों से कराया गया अवगत

बालाघाट। राष्ट्रबाण

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में मंगलवार को ग्राम पंचायत भटेरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं निशुल्क विधिक सहायता योजना एवं साईबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अधिकांश सायबर अपराध मानवीय लापरवाही के कारण होते है। इसलिए हमें सावधान एवं जागरूक रहने की आवष्यकता है। साथ ही श्री धुर्वे ने उपस्थित ग्रामीण जनों को घरेलू हिंसा अधिनियम व दहेज प्रतिषेद्य अधिनियम, प्रिलिटिगेषन मीडिएशन एवं लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी।

शिविर में मध्यस्थता की जानकारी देते हुए श्री धुर्वे ने बताया कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है, मध्यस्थ दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा कराता है। मध्यस्थता के लाभों के बारे में बताते हुए कहा गया कि विवादों का अविलम्ब एवं शीघ्र समाधान होता है, मध्यस्थता की प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय होती है, सामाजिक सद्भावना कायम रखने में सहायक होता है। शिविर में उपस्थित डिफेंस काउंसिल दुर्गेश लिमजे एवं चन्द्रेश नागेश्वर द्वारा डिफेंस काउंसिल योजना के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पैरालीगल वालेन्टियर एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहें।

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग द्वारा धारा-3(2) एवं संशोधित अधिनियम 1981 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त-2025 तक की अवधि को ÷मत्स्य प्रजनन काल÷ एवं वंश वृद्धि के संरक्षण के लिए बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस आदेश के सम्बंध में जिला मत्स्य अधिकारी श्रीमती पूजा रोडगे ने बताया प्रतिबंधित अवधि के दौरान समस्त नदियों एवं जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। बंद ऋतु के दौरान अवैधानिक मत्स्याखेट, परिवहन, क्रय, विक्रय आदि कार्यो में भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लघंन करेगा, तो वह दोष सिद्धि पर कारावास या जुर्माने से दण्डनीय होगा। नियमों के उल्लंघन में मत्स्य का परिवहन करने या उन्हें पकड़ने के लिए उपयोग में लाये गये।

जनसुनवाई में आयी भूमि संबंधी समस्याओं व विवादों की जांच करेंगे एसडीएम

6 माह पूर्व मांगी जानकारी नहीं देने पर, जिम्मेदार को जारी होगा नोटिस

बालाघाट। राष्ट्रबाण

कलेक्टर मृणाल मीना ने जनसुनवाई के दौरान भूमि सम्बंधी समस्याओं व शिकायतों के निराकरण के लिए सम्बंधित एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए है। मंगलवार को आयोजित हुई जनसुनवाई कलेक्टर श्री मीना की अध्यक्षता में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, एडीएम जीएस धुर्वे और एसडीएम गोपाल सोनी ने संयुक्त रूप से की। जनसुनवाई में आये आवेदनों के सम्बंध में अधिकारियों ने सम्बंधित विभागों से जानकारी प्राप्त की। जन सुनवाई में कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए।

जनसुनवाई में पेड़ काटने की अनुमति के लिए 6 माह पूर्व दिए आवेदन के मामले में कलेक्टर श्री मीना ने वारासिवनी एसडीएम श्री आरआर पांडे को संज्ञान लेने के निर्देश दिए है। साथ ही कहा कि कलेक्टर की ओर से भेजे गए पत्र का जवाब देने में इतनी लेट-लतीफी कैसे? एसडीएम इसकी जांच करें और जिम्मेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें।

कलेक्टर श्री मीना ने कटंगी के शुभम मेश्राम के आवेदन के सम्बंध में कटंगी एसडीएम श्री केसी ठाकुर को निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि आवेदक के पड़ोसी द्वारा शासकीय नाली पर शौचालय निर्माण के बारे में शिकायत की गई है। यदि अवैध है और इसके अलावा किसी अन्य का अवैध निर्माण है तो उस पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

लांजी में बिसोनी के नंदकिशोर रामटेककर ने कलेक्टर श्री मीना को बताया कि वो सीमांकन के लिए कई बार आये है लेकिन अब तक सीमांकन नही हुआ है।

कब्जे वाली भूमि पर मकान निर्माण से रोकने व धमकी देने की जांच की जाएगी

लांजी तहसील में बिरनपुर की डिलेश्वरी बसोने ने आवेदन में कलेक्टर श्री कहा कि उनकी कब्जे वाली भूमि पर वो मकान निर्माण करना चाहती है। लेकिन अन्य व्यक्ति द्वारा मकान निर्माण कार्य रोकने के लिए मारने पीटने की धमकियां दी जा रही है। कलेक्टर श्री मीना ने एसडीएम लांजी श्री कमलसिंह सिंहसार को मामलें की गंभीरता से जांच कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

कराते अकादमी चयन स्पर्धा का हुआ आयोजन

जिला मुख्यालय के साथ ही विभिन्न विकासखण्ड के भी प्रतिभागी हुए शामिल

बालाघाट। राष्ट्रबाण

मप्र शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के आदेशानुसार खेलो बढ़ो अभियान के तहत जिले में जिला स्तर कराते अकादमी चयन स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में जिले के विभिन्न विकास खंडों और जिला मुख्यालय के खिलाड़ियों ने भाग लिया।

मप्र मार्शल आर्ट अकादमी के प्रमुख कोच और सहप्रशासक श्री हर्षित विश्वकर्मा ने खिलाड़ियों का कराते स्किल टेस्ट और कराते खेल की विभिन्न विधाओं का परीक्षण लिया। चयन स्पर्धा में 13 से 20 वर्ष आयु के बालक और बालिका कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ियों को 26, 27 और 28 जून को राज्य स्तर चैनल स्पर्धा में भाग लेने के लिए टीटी नगर स्टेडियम भोपाल जाना होगा। द्वितीय राज्य स्तर की चयन स्पर्धा 1 दिन की होंगी। राज्य चैनल स्पर्धा के लिए खिलाड़ियों को अपने आने-जाने परिवहन व भोजन के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होंगी। अकादमी में चयन होने के पश्चात सभी सुविधाएं मेडिकल, पढ़ाई आदि विभाग द्वारा प्रदान की जाएंगी। जिला स्तर पर इस आयोजन में सहयोग के लिए जिला खेल प्रशिक्षक सजिन्द्र कृष्णन, कार्यालय प्रभारी कैदारनाथ ठाकरे, खेल युवा समन्वयक राजेश बंम्बुरे और अन्य उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायत ददिया का मामला...

निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत, ठेकेदार कर रहा काम

लालबर्रा। राष्ट्रबाण

जनपद मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत ददिया में गौण खनिज मद से पिछले वर्ष 15 लाख रूपयों की लागत से बाउंड्री वाल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। जिसमें ग्राम सरपंच-सचिव और अन्य ग्रामीण जन उपस्थित भी हुए।

उक्त निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संबंधित विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को सौंपी गई किंतु सरपंच और सचिव द्वारा यह कार्य ठेकेदार को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से10 -15 त्नकी कमीशन खोरी की गई है। इसके बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अपने आप ही सवालिया निशान उठाना लाजिम हो जाता है। बहरहाल अभी निर्माण कार्य रुका हुआ है। जिस संबंध में सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र भलावी ने दूरभाष पर बताया कि विभाग द्वारा पर्याप्त पेमेंट नहीं किया गया है फिर भी ठेकेदार द्वारा पेमेंट की तुलना में अधिक काम कर दिया गया है। यहां पर यह बात समझना बहुत जरूरी होगा कि अनेक कार्यों की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होती है लेकिन वे लोग कमीशन खोरी के चक्कर में ठेकेदारों को काम दे देते हैं जिससे गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं हो पाता और कुछ ही सालों में वह कार्य धराशाही हो जाता है। इन सब बातों की जानकारी जनपद स्तर पर पदस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को भी होती है लेकिन कई वर्षों से पंचायत के काम में ठेकेदारी करने वाले ठेकेदार अपना काम करवाने के लिए स्वयं ही जनपद आते रहते हैं जो सब अधिकारी कर्मचारी और बाबू से ऐसे संबंध बना लेते हैं कि एक ठेकेदार काम तो हो जाएगा लेकिन सरपंच और सचिव को उसी काम के लिए दो और तीन दिनों तक चक्कर काटने पड़ सकते हैं तो फिर ऐसी चिक्लस में पड़ने से बेहतर उनके द्वारा यह समझा जाता है कि ठेकेदार साहब तुम ही ऑफिस जाओ और तुम ही सारा काम करवाओ। हमें तो बस बैठे-बैठे कमीशन मिल जाए यही बहुत काफी है।

ग्राम पंचायत ददिया बना ठेकेदारों का अड्डा।

ठेकेदार द्वारा बनाई गई बाउंड्रीबाल।

राष्ट्रबाण
सिवनी, बुधवार 11 जून 2025

सिवनी-बैतूल राष्ट्रबाण

● बरघाट ● छपारा ● धनोरा ● घंसौर ● केवलारी ● कुरई ● लखनादौन ● सिवनी ग्रामीण ● मुलताई ● बैतूल बाजार ● आमला ● भैंसादंड ● सारणी ● बोरदई ● आठनेर

भ्रष्टाचार के नाम पर मध्यप्रदेश का राजस्व विभाग प्रथम स्थान में आता है और वही जिला मुख्यालय में तहसील भाग दो में भ्रष्टाचार और लापरवाही की चर्चा किसी से छुपी नहीं है। आम शब्दों में कहे तो भ्रष्टाचार पुरस्कार होता तो सिवनी तहसील भाग दो प्रथम स्थान से सम्मानित होती।

नीलेश चोखे, रीडर
बिन लक्ष्मी न काम हो भाया।

तहसीलदार की टेबल के सामने से बाबू ले रहे रिश्वत

...हे प्रभु इनसे कौन न्याय दिलाएगा?

आखिर पंकज राय को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही डूडासिवनी पुलिस

मामला डूंडा सिवनी (ग्रामीण) थाना अंतर्गत है कि दिनांक 05 फरवरी 2025 एफआईआर क्रमांक 0059/2025 का है। जहां पर पंकज राय पिता किशोर राय निवासी गोकुल विहार बारापत्थर सिवनी के द्वारा बींझावाडा रोड ऑल सेन्स स्कूल के सामने खसरा नंबर 432/157 रकबा 0.01 हेक्टेयर 1500 वर्गफुट जमीन को स्वंय की बातकर मेहेरून्निशा अंसारी निवासी ज्यारत नाका सिवनी को पंजीयन बैनामा करके बेच दिया। मामला तब उजागर हुआ जब पंकज राय द्वारा विक्रय की गई रजिर्स्टड जमीन का कब्जा मेहेरून्निशा अंसारी को नही दिया जा रहा था। हर बार सीमांकन कराने के बाद कब्जा देने के लिए कहकर टाला जा रहा था। तब मेहेरून्निशा अंसारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिवनी को प्रकरण की जानकारी दी गई तो पता चला कि यह मामला फर्जी फौती बनवाकर फर्जी वसीयतनामा तैयार करके जमीन अपने नाम पर करवा लिया। फिर वह जमीन को मेहेरून्निशा अंसारी को विक्रय कर दिया। वास्तविक में भूमि स्वामी चेतराम राय है जोकि जीवित है।

सिवनी। राष्ट्रबाण

यहां पर स्थित बाबू एवं चपरासी अपने आप को किसी अधिकारी से काम नहीं समझते और समझे भी क्यों न आखिर इनके हिसाब से ही अधिकारी अपना काम करते हैं। जिस प्रकरण में आवेदक द्वारा पैसे या प्रभावशाली व्यक्ति से बाबू को फोन आ जाए तो उस प्रकरण में बाबू इतनी रुचि रखते हैं, कि वह साहेब की टेबल के ऊपर प्रकरण नजर आ जाएगा। मजह पहली पेशी के एक से दो दिन में ही बाबू के द्वारा तहसीलदार के द्वारा प्रकरण के आदेश में हस्ताक्षर करवा लेते है। वही यदि आवेदक द्वारा पैसे नहीं दिया है, तो प्रकरण नीचे दबाने में यह में बाबू एवं चपरासी बहुत माहिर होते है। जब तक इनका मकसद पूरा नहीं होता तब तक आवेदक को अपने दफ्तर के चक्कर में चक्कर लगवाते रहते हैं। फिर यदि बाबू से प्रकरण के बारे में पूछा जाता है, तब बाबू टाला मोटली करके पूरी जवाबदेही तहसीलदार के ऊपर डाल देता है। मेरा काम आदेश बनाने का है, बाकी तहसीलदार से ऊपर है, यह जबाव होते भ्रष्ट बाबुओ के।

कभी यदि कलेक्टर साहिबा वक्त निकलकर तहसील कार्यालय की वास्तविकता जाने के लिए औचक निरीक्षण करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस कलेक्टर साहिबा, आंख बंद करके 50 फाइल का बारीकी से अवलोकन करे तो पूरी सच्चाई सामने जा जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रकरण में पैसे नहीं मिलते हैं उस प्रकरण में पेशी की तारीख में तारीख मिलिंगी और अंत में प्रकरण में रुचि न लेने के वजह से लिखकर प्रकरण को खारिज किया जाता है।

तहसीलदार के नाम पर बनाया दबाव!

जब राष्ट्रबाण के द्वारा पटवारी गौरीशंकर साहू से बात की गई तो पता चला कि बाबू निलेश चोखे द्वारा तहसीलदार के नाम से दबाव बनाया जा रहा था कि प्रकरण देखकर रिपोर्ट पेश करें। फिर पटवारी के द्वारा विरोध करने पर लगातार मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा था। फिर मजबूरन प्रकरण देखकर मेरे द्वारा रिपोर्ट दे दी गई। बात समझ से परे है कि जब रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण के लिए बाबू इतनी बारीकी से दस्तावेज देखता है और पटवारी प्रतिवेदन का इंतजार करता है। फिर पंकज राय के मामले पर बाबू ने इतनी रुचि के साथ लापरवाही कैसे किया। जमीन किसी और की कागज में उसे मृत बताकर जगह किसी और के नाम कर दिया यह कारनामा मामूली नहीं। आखिर पंकज राय और बाबू निलेश चोखे के कैसे मधुर संबंध हैं, जिस वजह से प्रकरण को आंख बंद करके बिना किसी भय के फर्जी फौती एवं वसीयत बनवाकर पास कर दिया। इस प्रकरण में यदि पंकज राय गिरफ्तार होता है तो मामले की सच्चाई उजागर हो जाएगी और चौखे बाबू की भूमिका भी स्पष्ट हो जाएगी ?

बाबूराज की गिरफ्त में फंसे जिम्मेदारों के कार्यालय।

वन विद्यालय कालापाठा में कार्यशाला का आयोजन

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम वन विद्यालय कालापाठा में कार्यशाला का आयोजन।

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत कार्यशाला आयोजित

बैतूल। राष्ट्रबाण

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को वन विद्यालय कालापाठा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान डीपीसी जितेन्द्र कुमार भनारिया द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया।

कार्यशाला में जिले भर के ब्लॉक सह-समन्वयक एवं संकुल सह-समन्वयक शामिल हुए। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में सर्वे, प्रचार प्रसार, अक्षरसाथी का चयन, परीक्षा पूर्व की तैयारी, मूल्यांकन एवं मॉडल सामाजिक चेतना केन्द्र के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। मंच संचालन नेमीचंद मालवीय ने किया। उक्त कार्यशाला में जिले से विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैतूल नवीन प्रहलादी, प्रभात पट्टन विकासखंड शिक्षा अधिकारी आशीष शर्मा, सहायक परियोजना समन्वयक राजेश तुरिया, लेखा वित्त अधिकारी गणेश प्रसाद सोनी, जि.सह समन्वयक कुशलेश धाड़से, बीआरसी बैतूल श्री दुर्गेश रघुवंशी, आमला बीआरसी मनीष धोटे एवं ब्लॉक सह समे न्वयकों में राजेश झाडे, गणेश देशमुख, संजय सूर्यवंशी, राजेश निरापुरे, प्रवीण नरवरे, सेवाराम गायकवाड़, मनीष हुरमाड़े, अजय लाल, कल्पनाथ भारद्वाज, श्रीमती निलिमा शर्मा एवं समस्त संकुल सह समन्वयक उपस्थित रहे।

तहसीलदार पर अवैध बंटवारा और मकान तोड़ने का आरोप

अपर कलेक्टर ने दिए एक सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश

शंकरलाल मालवीय, पीड़ित।

बैतूल। राष्ट्रबाण

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में लोहिया वार्ड निवासी शंकरलाल मालवीय ने गंभीर आरोप लगाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए उनके विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं 1966 के तहत कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय से इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल को निर्देश जारी कर एक सप्ताह के भीतर जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है।

शंकरलाल ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि उनकी परिवर्तित भूमि मौजा हमलापुर के खसरा नंबर 219/71 रकबा 0.016 हेक्टेयर और खसरा नंबर 219/121, 219/206 है। उन्होंने बताया कि इस भूमि से संबंधित बंटवारा आदेश राजस्व प्रकरण क्रमांक 204/अ-27 वर्ष 2016-17 में दिनांक 28 मई 2018 को किया गया था। इस आदेश से जुड़ी जानकारी उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 30 नवंबर 2021 को मांगी थी, लेकिन उन्हें आज तक कोई सूचना नहीं दी गई।

आवेदक ने यह भी बताया कि इसी भूमि के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 08/ब/121 वर्ष 2018-19 में दिनांक 22 अप्रैल 2019 को उनके मकान को अवैध रूप से तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही में किन धाराओं और नियमों के तहत तहसीलदार को अधिकार प्राप्त थे, इसकी भी जानकारी उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत 20 सितंबर 2021 को मांगी थी, परंतु इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला।

शंकरलाल मालवीय का आरोप है कि तहसीलदार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भूमि का अवैध रूप से बंटवारा किया, उनके आवासीय भूखंड पर बने मकान को भी तोड़ डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि भू- राजस्व संहिता में कहीं भी तहसीलदार को आवासीय भूखंडों का बंटवारा करने अथवा मकान तोड़ने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर यह कार्य किया। शंकरलाल ने अपने आवेदन में इस पूरे मामले की तत्काल जांच कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति भी संलग्न की गई है।

तिलक स्कूल में नहीं थम रही प्राचार्य की मनमानी

शौचालय मरमत कार्य में लापरवाही, कमीशन में मांगे 10 हजार

पहले कबाड़ा बेचने के लग चुके है आरोप

गंगाराम साकुरे, प्राचार्य : शिक्षा जाए भाड़ में नोट कमाओ आड में?

सिवनी। राष्ट्रबाण

सिवनी नगर में तिलक हाई स्कूल में प्राचार्य गंगाराम सकुरे का नाम अकसर विवादों में रहता है। कभी यह अपने कार्यालीन समय से पहले स्कूल से जाने को लेकर सुर्खिया बटोरते है तो कभी स्कूल में हो रहे निर्माण कार्यो में कमीशन और कबाड़ बेचने के लिए चर्चित रहते है। वर्तमान में प्राचार्य गंगाराम साकुरे स्कूल में शौचालय मरमत कार्य में 10 रूपये के कमीशन को लेकर चर्चा में है।

तिलक हाई स्कूल, स्कूल बदनाम हुआ प्राचार्य तेरे लिए।

तीन बच्चों की शिकायत भी लंबित

शिक्षा विभाग में तीन बच्चो के प्रकरण में तिलक स्कूल के प्राचार्य गंगाराम साकुरे की शिकायत नगर के एक युवक द्वारा की गई है। इस प्रकरण पर जिला शिक्षा अधिकारी को जाँच के लिए निर्देशित किया गया है लेकिन इसे सिस्टम की खराबी ही कहेंगे की महीनो से यह जाँच शिक्षा विभाग में धूल खा रही है लेकिन इस शिकायत पर विभाग द्वारा जाँच पूरी नहीं की जा रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो प्राचार्य गंगाराम ने इस शिकायत पर जाँच अधिकारी को मैनेज कर आर्थिक लाभ पहुँचाया है जिसके चलते विभाग द्वारा जाँच को लंबित कर रखा गया है।

जानकारों की माने तो स्कूल में शौचालय की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए 50 हजार रूपये की राशि शासन द्वारा दी गई। सूत्रों की माने तो शौचालय मरमत कार्य में प्राचार्य द्वारा 10 हजार का कमीशन मांग कर एक शिक्षक को यह दे दिया गया। कमीशन से मिले काम में शिक्षक द्वारा मनमानी कार्य करते हुए घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस कार्य को महज 10 से 15 हजार में निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जब प्राचार्य गंगाराम साकुरे से संपर्क किया गया तो वह इस मामले में कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सके, बल्कि रिपोर्टर से क्या समस्या है पूछने लगे।

प्राचार्य द्वारा सामने से घटिया कार्य संरक्षण दे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दे की पूर्व भी तिलक स्कूल में निर्माण कार्य में एक भाजयुमो नेता के साथ मिलकर जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। सूत्र बताते है की उस कार्य में भाजयुमो के द्वारा 10 प्रतिशत का कमीशन प्राचार्य को देकर निर्माण कार्य में खुला भ्रष्टाचार किया गया था। भाजयुमो नेता और प्राचार्य ने मिलकर शासकीय धन से होली खेलते खूब लूट मचाई।

पहले भी लगे है आरोप

तिलक स्कूल के प्राचार्य गंगाराम साकुरे कोई पहली बार विवादों में नहीं आये है, इसके पूर्व में गंगाराम साकुरे पर स्कूल से कबाड़ बेचने के आरोप लग चुके है। सूत्र बताते है की गंगाराम साकुरे ने बिना कोई निविदा प्रकाशन के लाखो का कबाड़ बेच दिया। इस मामले की जानकारी आज तक विभाग को नहीं है या यूं कहे की शिक्षा अधिकारी सब कुछ जानकर अनजान बने हुए है। तो गंगाराम साकुरे के प्राचार्य रहते हुए तिलक स्कूल के छात्रों के द्वारा पुताई का मामला सामने आया था जिसमे वीडियो पर छात्र पुताई करते स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस मामले को राष्ट्रबाण द्वारा प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने जाँच के निर्देश दिए थे। प्राचार्य की लचर और लापरवाह कार्यप्रणाली का ही परिणाम है की तिलक स्कूल का रिजल्ट ख़राब आया। स्कूल में मात्र छः छात्र ही उत्तीर्ण हुए।

बहन की संदिग्ध मौत पर भाई ने लगाए ससुराल वालों पर हत्या के आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार

साहब! मेरी बहन की ससुराल वालों ने हत्या की है...

बैतूल। राष्ट्रबाण

बोरदेही थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत को लेकर मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में मृतका के परिजनों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी से शिकायत की है। मुलताई थाना क्षेत्र अंतर्गत माथनी निवासी जयचन्द मोहबे ने अपनी बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर ससुराल पक्ष के चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

जयचन्द ने बताया कि उसकी बहन गायत्री का विवाह ग्राम माथनी में 20 अप्रैल 2021 को पप्पू पिता दीनू बामने निवासी ग्राम कुजबा के साथ हुआ था। पप्पू के साथ उसके परिवार में देवेन्द्र बामने, मां भागवंती बामने और पिता दीनू बामने रहते हैं। इन चारों पर हत्या का आरोप लगाया गया है।

आवेदक जयचन्द के अनुसार विवाह के कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में पूरे परिवार ने गायत्री को दहेज के लिए ताने देने शुरू कर दिए। कहा गया कि तुम्हारा परिवार कंगाल है और उन्होंने शादी में कुछ नहीं दिया। बार-बार 50 हजार रुपए की मांग की गई। गायत्री ने यह जानकारी कई बार अपने मायके आकर या फोन पर दी थी। मजबूरी में मायके वालों ने 50 हजार रुपए भी दिए थे, जिनसे पप्पू ने ट्रैक्टर खरीदा, लेकिन बाद में रुपए भी वापस नहीं किए और मारपीट शुरू कर दी।

जयचन्द ने बताया कि पप्पू किसी अन्य महिला से फोन पर बात करता था, जिससे गायत्री को मानसिक प्रताड़ना होती थी। विरोध करने पर पप्पू शराब पीकर घर आता और उसे पीटता। एक बार तो उसने यह भी कहा कि जबरन तेरे साथ शादी की है।

11 मई 2025 को गायत्री मायके आई थी। उसी दिन रात करीब 11 बजे पप्पू उसे लेने आया, तो परिवार ने कहा सुबह चले जाना। पप्पू ने वहीं गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने दौड़ा। बीच बचाव से मामला शांत हुआ और 12 मई को गायत्री वापस ससुराल चली गई। इसके बाद 20 मई को गायत्री ने किसी और के मोबाइल से फोन कर बताया कि उसके साथ फिर मारपीट की गई है। फिर फोन बंद हो गया और उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। पप्पू और उसका परिवार गायत्री से बात नहीं करवाते थे और नंबर ब्लॉक कर दिया गया था।

28 मई को दोपहर 12.45 बजे पप्पू के मोबाइल से फोन आया। फोन पर उसके ससुर दीनू ने बताया कि गायत्री पापड़ डालते हुए बेहोश हो गई है और उसे इलाज के लिए मुलताई अस्पताल ला रहे हैं। जब जयचन्द और परिवार वाले अस्पताल पहुंचे तो देखा कि गायत्री मृत है और उसके मुंह से खून निकल रहा था, शरीर पर चोटों के निशान थे।

गायत्री के ससुर ने कहा कि पापड़ डालते समय बेहोश हुई, वहीं देवेन्द्र ने कहा कि कपड़े प्रेस करते समय करंट लगा। दोनों के बयान अलग-अलग थे, जिससे संदेह और गहरा गया।

बैतूल में पत्नी ने युवती को बीच सड़क पर पीटा

पति से फोन पर बात करने से नाराज थी; बाल खींचकर 10 मिनट तक कारण पूछती रही

बैतूल। राष्ट्रबाण

बैतूल के लल्ली चौक पर एक महिला ने एक दुकान में काम करने वाली युवती की जमकर पिटाई कर दी। खंजरपुर की रहने वाली महिला ने युवती को अपने पति से फोन पर बात करने के कारण पीटा। महिला ने युवती को लल्ली चौक के पास देखते ही पकड़ लिया। उसने युवती के बाल पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। युवती लगातार छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन महिला ने उसे नहीं छोड़ा। घटनाक्रम करीब 10 मिनट तक चलता रहा।

वायरल किया वीडियो

वीडियो में महिला, युवती से कह रही है कि उसने पहले भी पति से बात न करने के लिए बोला था। घटना के दौरान वह बार-बार युवती से पूछती रही कि वह उसके पति से क्यों बात करती है। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कोतवाली थाना प्रभारी रविकांत डहरिया ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक संजय बघेल द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एमपी नगर भोपाल म.प्र से मुद्रित कराकर शिवनगर कॉलोनी सड़क मोहल्ला मरझोर जिला सिवनी से प्रकाशित।
RNI NO.: MPHIN/2015/72804 , **संपादक* संजय बघेल** पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त विवादों का निपटारा न्यायलयीन क्षेत्र सिवनी होगा। E-mail: rashtrabaan@gmail.com. mob: 7000427433